3

धार्मिक आयोजनों से सामाजिक समरसता

5

वैचारिक दृढ़ता और संगठनात्मक समर्पण का जीवन

7

खेलो एमपी चयन ट्रायल में उभरी ग्रामीण खेल

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 37 प्रति सोमवार, 19 जनवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश भाजपा में बढ़ती अंतर्कलह पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की परीक्षा

कई मंत्रियों के ओएसडी की कार्यप्रणाली से कटघरे में मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सियासी अंतर्कलह सतह पर आती दिखाई दे रही है। सत्ता में लंबे समय से काबिज भाजपा में अब नेतृत्व, प्रभाव और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर भीतर ही भीतर चल रही खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में नेताओं के बीच बढ़ते गुट, परस्पर अविश्वास और संगठनात्मक संतुलन बिगड़ने की आशंकाओं ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा के भीतर बढ़ती खींचतान का असर अब मंत्रियों के कार्यालयों तक भी पहुंचता दिख रहा है। अब संगठन के पास मोहन सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और उनके ओएसडी की रिपोर्ट पहुंची है, जो दर्शाती है कि इनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। साथ ही इन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं किये जाने के आरोप हैं। जगत विजन ने अनेकों बार प्रदेश के भ्रष्ट मंत्रियों के कारनामों को उजागर किया था और सरकार को भी सचेत किया कि इनकी कार्यप्रणाली से पार्टी और सरकार की छबि खराब हो रही है। पार्टी और सरकार के गलियारों में यह माना जा रहा है कि ओएसडी के माध्यम से ही कई मंत्री अपने–अपने राजनीतिक एजेंडे और गुटीय संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। चर्चा है कि विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल सहित कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के ओएसडी में जल्द बदलाव हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय भी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। लेकिन उन पर आज तक ऐसी कोई आंच नहीं आयी है। क्योंकि उन्हें पार्टी की मर्यादा और अनुशासन का पता है। उनकी कार्यप्रणाली से सत्ता या संगठन को नीचा नहीं देखना पड़ा है। आज इन बेलगाम मंत्रियों को विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ मंत्रियों से सीख लेने की जरूरत है। संगठन के इशारे पर होने वाले ये संभावित परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी माने जा रहे हैं। सागर, जबलपुर और विंध्य जैसे प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों से आ रही खबरें संगठन के लिए चेतावनी की घंटी मानी जा रही हैं। (शेष पेज 2 पर)

गरीब कल्याण का संवेदनशील मॉडल:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई सामाजिक दिशा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक प्राकृतिक संपदा, आदिवासी संस्कृति और सरल जनजीवन के रूप में रही है। परंतु बीते दो वर्षों में इस राज्य ने एक और पहचान अर्जित की है संवेदनशील और परिणामदायी गरीब कल्याण के मॉडल के रूप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में समाज के कमजोर, वंचित और विशेष जरूरतों वाले वर्गों के जीवन में जो बदलाव आया है, वह केवल योजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि शासन की सोच और प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह कार्यकाल बताता है कि जब सरकार नीति को कागज से निकालकर जमीन पर उतारने का संकल्प लेती है, तब कल्याण योजनाएँ आंकड़ों से आगे बढ़कर मानवीय गरिमा का आधार बनती हैं। छत्तीसगढ़ ने सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, उभयलिंगी समुदाय के पुनर्वास और नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति दर्ज की है, वह देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुकी है।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की शह पर बेलगाम इंटेलीजेंस आईजी अमित कुमार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के कारनामें दिन-प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विभाग में पदस्थापना और तबादलों में भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। ताजा मामला प्रदेश के इंटेलीजेंस आईजी अमित कुमार को लेकर सामने आया है। इंटेलीजेंस आईजी सरकार का सबसे करीबी और प्रमुख पद है। अमित कुमार पहले दिल्ली में थे। प्रदेश में बीजेपी के शासन में आते ही छत्तीसगढ़ आ गये। यहां वह इंटेलीजेंस आईजी पद पर आये हैं। लेकिन कार्यभार संभालते ही इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदेश का पूरा खुफिया विभाग फैलियर हो गया है। इनके कार्यकाल में बलौदा बाजार की घटना हुई, रायगढ़ कांड, बैंकुठपुर कोल माइंस कांड, बिलासपुर नरेश साहू हत्याकांड राजनांदगांव में यादव हत्या काण्ड, कवर्धा बलात्कार कांड, कांकेर में आदिवासी कांड, ईसाई कांड, (कांकेर) धर्मांतरण मामला, डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के मामले में इनकी इंटेलीजेंस शून्य साबित हुई। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई सामाजिक दिशा

पेंशन योजनाओं में भरोसे की नई सुबह

गरीब और असहाय वर्गों के लिए पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और सम्मान का सहारा होती है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छह प्रमुख पेंशन योजनाओं- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, सामाजिक सुरक्षा, सुखद सहारा और मुख्यमंत्री पेंशन योजना को तकनीकी सुधारों के माध्यम से नई मजबूती दी। इन योजनाओं के जरिए 21.99 लाख हितग्राहियों तक सहायता पहुँचना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। डीबीटी के माध्यम से 98 प्रतिशत भुगतान और 96 प्रतिशत आधार सीडिंग ने पेंशन प्रणाली को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया। ई-केवायसी के जरिए मृत और अपात्र हितग्राहियों को हटाकर वास्तविक पात्रों को लाभ दिलाना प्रशासनिक सजगता का परिचायक है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में हितग्राहियों की संख्या 7.10 लाख से बढ़कर 7.45 लाख होना इस बात का संकेत है कि सरकार ने पात्रता का दायरा बढ़ाकर अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच बनाई।

राष्ट्रीय परिवार सहायता

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आकस्मिक मृत्यु किसी बड़े आर्थिक संकट से कम नहीं होती। इस दर्द को समझते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत दो वर्षों में 5,110 परिवारों को 20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की। यह योजना उन परिवारों के लिए संबल बनी, जो अचानक जीवन की विषम परिस्थितियों में असहाय हो जाते हैं।

सहानुभूति से आत्मनिर्भरता तक

मुख्यमंत्री साय के कार्यकाल में दिव्यांगजन कल्याण को प्राथमिकता का विषय बनाया गया। यूडीआईडी कार्ड लाभार्थियों की संख्या 2.74 लाख तक पहुँचना यह दर्शाता है कि सरकार ने पहचान और अधिकार दोनों को सुनिश्चित किया। सहायक उपकरण वितरण 1,161 से बढ़कर 3,609 होना केवल संख्या नहीं, बल्कि हजारों जीवनों में आई सुविधा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। सामर्थ्य विकास शिविरों के माध्यम से 4,983 दिव्यांगजनों को सीधे लाभ मिला। ये शिविर न केवल सहायता का माध्यम बने, बल्कि समाज में समान अवसर की भावना को भी सशक्त करते हैं।

शिक्षा भविष्य की नींव

विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। सरकारी विशेष विद्यालयों में 1,342 और स्वैच्छिक संस्थाओं के विद्यालयों में 3,049 विद्यार्थियों की पढ़ाई यह दर्शाती है कि सरकार ने समावेशी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। माना कैम्प स्थित फिजिकल रिफरल रीहैब सेंटर और सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब की सेवाओं का विस्तार लगभग दोगुना होना यह सिद्ध करता है कि सरकार केवल नीतियाँ नहीं बना रही, बल्कि सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ शिक्षा से जुड़े रहने का मजबूत माध्यम बनीं। राज्य छात्रवृत्ति 7,807 से बढ़कर 8,726 और केंद्रीय छात्रवृत्ति 390 से बढ़कर 423 होना यह दर्शाता है कि शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान की यात्रा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करना वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का सशक्त उदाहरण है। आईआरसीटीसी के सहयोग से अब तक 6 यात्राओं में 4,697 वरिष्ठजन लाभान्वित हुए। वर्ष 2025-26 के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान यह दर्शाता है कि यह योजना निरंतर और व्यापक रूप में आगे बढ़ेगी। यह पहल केवल यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान और आध्यात्मिक संतोष का अवसर है।

स्वरोजगार और ऋणमाफी आत्मनिर्भरता की राह

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2,435 हितग्राहियों को रियायती ऋण और 411 को उत्थान सब्सिडी दी गई। साथ ही 24.50 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर सरकार ने यह संदेश दिया कि संवेदनशील शासन केवल सहायता नहीं देता, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम करता है। घरौंदा, हाफ-वे होम, अपराजिता और प्रशामक गृहों में बढ़ती हितग्राही संख्या यह दर्शाती है कि राज्य ने जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित आश्रय का मजबूत तंत्र विकसित किया है। मानसिक रोग से उबर चुके व्यक्तियों और बहुदिव्यांगजनों के लिए यह पहल अत्यंत मानवीय है।

पहचान से सम्मान तक

छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहाँ उभयलिंगी समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाए गए। पहचान प्रमाण पत्र 506 से बढ़कर 915 होना और एसआरएस ऑपरेशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़ना सरकार की सामाजिक समावेश की सोच को स्पष्ट करता है। नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 11 से बढ़ाकर 25 करना और 4,379 लोगों को लाभ देना समाज सुधार की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। सियान हेल्पलाइन पर 2.73 लाख कॉल यह बताती हैं कि सरकार ने भरोसेमंद संवाद का मंच दिया है।

भविष्य की ठोस तैयारी

सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान, 205 करोड़ की आधारभूत संरचना, दिव्यांग आयोग का गठन और बढ़ा हुआ बजट- ये सभी कदम बताते हैं कि मुख्यमंत्री साय की सरकार केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य को भी मजबूत कर रही है। इन दो वर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील शासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुँचाने का संकल्प है। छत्तीसगढ़ आज गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल बनकर उभरा है, जहाँ शासन केवल प्रशासन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का पर्याय बन गया है।

मध्यप्रदेश भाजपा में बढ़ती अंतर्कलह पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की परीक्षा

(पेज 1 का शेष)

सागर में तीन दिग्गजों के बीच बढ़ता तनाव

सागर संभाग में भाजपा की अंदरूनी राजनीति सबसे अधिक चर्चा में है। यहां वरिष्ठ नेता और लंबे समय से गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच बढ़ते तनाव ने संगठन की चिंता बढ़ा दी है। तीनों नेताओं की अपनी–अपनी राजनीतिक, समर्थक वर्ग और प्रशासनिक पहुंच है। ऐसे में क्षेत्रीय निर्णयों, नियुक्तियों और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर उनके बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आने लगी है।

जबलपुर में नेताओं के करीबी आमने–सामने

जबलपुर संभाग में भी पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, मंत्री राकेश सिंह और विधायक अभिलाष पांडे के करीबी नेताओं के बीच खींचतान तेज हो गई है। प्रत्यक्ष टकराव भले ही शीर्ष नेतृत्व के बीच न हो, लेकिन उनके समर्थक और निचले स्तर के नेता लगातार एक–दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। संगठनात्मक फैसलों, नगर और जिला स्तर की भूमिका को लेकर असंतुलन की स्थिति बन रही है। पार्टी के कार्यक्रमों में मंच साझा करने से लेकर स्थानीय मुद्दों पर अलग–अलग सुर में बयानबाजी यह संकेत दे रही है कि भीतरखाने खाई गहरी हो रही है।

विंध्य में भी बढ़ने लगी बेचैनी

विंध्य क्षेत्र में भी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक अभय मिश्रा और वरिष्ठ नेता जनार्दन मिश्रा के बीच बढ़ती राजनीतिक असहजता की चर्चा सियासी गलियारों में है। क्षेत्रीय प्रभाव, संगठन पर पकड़ और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर मतभेद उभर रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर सभी नेता एकजुटता का संदेश देते नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी स्तर पर समर्थकों के बीच प्रतिस्पर्धा और असंतोष संगठनात्मक समन्वय को प्रभावित कर रहा है।

संगठन की भूमिका और बढ़ती चुनौती

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस बढ़ती अंतर्कलह को समय रहते नियंत्रित किया जाए। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा यह संदेश देता रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि हालिया बदलावों और संभावित फेरबदल के जरिए संगठन यह दिखाना चाहता है कि अनुशासन सर्वोपरि है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल ओएसडी बदलने या कुछ प्रशासनिक फैसलों से गहरे राजनीतिक मतभेद खत्म हो पाएंगे?

कार्यकर्ताओं में भी बढ़ रहा असमंजस

नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान का सीधा असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा है। अलग–अलग गुटों में बंटे कार्यकर्ता यह समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ खड़ा होना संगठनात्मक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। इससे जमीनी स्तर पर सक्रियता और समन्वय प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही है। भाजपा की ताकत हमेशा उसका कैडर आधारित ढांचा रहा है। लेकिन जब ऊपर के स्तर पर खींचतान बढ़ती है, तो उसका असर नीचे तक जाता है। यही वजह है कि संगठन नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर मंथन में जुटा है। अब देखने वाली बात यह है कि संगठन के इशारे पर होने वाले इन परिवर्तनों से वास्तव में क्या बदलाव देखने को मिलता है। क्या गुटीय राजनीति पर लगाम लगेगी या यह केवल अस्थायी संतुलन साबित होगा? क्या शीर्ष नेतृत्व सख्त संदेश देकर सभी नेताओं को एकजुट करने में सफल होगा? मध्यप्रदेश भाजपा के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती सत्ता में रहते हुए संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की है। यदि समय रहते इस बढ़ती अंतर्कलह को नहीं संभाला गया, तो यह न केवल संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर डाल सकती है। फिलहाल सियासी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा नेतृत्व इस अंदरूनी चुनौती से कैसे निपटता है और क्या पार्टी अपनी पारंपरिक एकजुटता को फिर से स्थापित कर पाती है या नहीं?

नींद की गड़बड़ी और कैंसर के बीच छुपा संबंधः वैज्ञानिकों के शोध से नया खुलासा

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल लगातार चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े अहम विषयों पर नई जानकारी सामने आ रही है। इसी क्रम में, एम्स भोपाल के जैवरसायन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण शोध में नींद की गड़बड़ी और कैंसर के बीच छिपा हुआ गहरा संबंध सामने आया है। यह शोध डॉ. अशोक कुमार द्वारा डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव (केजीएमयू लखनऊ), मनेन्द्र सिंह तोमर और मोहित के सहयोग से किया गया है। यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्लीप मेडिसिन रिव्यूज में प्रकाशित हुआ है। इस महत्वपूर्ण शोध के लिए डॉ. अशोक कुमार को एम्स भोपाल में आयोजित चौथे रिसर्च डे के दौरान फैकल्टी श्रेणी में बेस्ट पेपर अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया।

शोध में बताया गया है कि मानव शरीर एक प्राकृतिक दिन-रात के चक्र पर काम करता है, जिसे जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यही चक्र हमारी नींद, हार्मोन, पाचन प्रक्रिया, ऊर्जा स्तर और रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। अध्ययन के अनुसार, जब यह चक्र बिगड़ता है, जैसे देर रात तक जागना, नाइट ड्यूटी करना या लगातार शिफ्ट में काम करना, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने का अवसर मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कैंसर कोशिकाएं शरीर की ऊर्जा प्रणाली को अपने लाभ के लिए बदल लेती हैं, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाएं उन्हें नष्ट नहीं कर पातीं।

यह शोध आम नागरिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैंसर की रोकथाम केवल दवाओं तक सीमित नहीं है। जीवनशैली में सुधार, जैसे नियमित और पर्याप्त नींद, समय पर भोजन और संतुलित दिनचर्या, कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में कैंसर का इलाज अधिक व्यक्तिगत होगा, जिसमें मरीज की नींद, दिनचर्या और जैविक घड़ी को ध्यान में रखकर उपचार तय किया जाएगा। इससे इलाज अधिक प्रभावी होगा और दवाओं के दुष्प्रभाव भी कम हो सकते हैं।

आम जनता के लिए संदेश है कि नियमित समय पर सोना और जागना, देर रात मोबाइल और स्क्रीन से दूरी रखना, तथा भोजन और व्यायाम का समय तय करना बेहद आवश्यक है। स्वस्थ जीवनशैली न केवल सामान्य बीमारियों से बचाव करती है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ भी एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकती है।

इस अवसर पर एम्स भोपाल में कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ प्रो. (डॉ.) माधवानन्द कर ने कहा, "एम्स भोपाल लगातार चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। डॉ. अशोक कुमार और उनकी टीम द्वारा नींद और कैंसर के बीच छुपे संबंध पर किए गए शोध ने समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यह शोध न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यवान है, बल्कि आम जनता के लिए जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में भी मार्गदर्शक साबित होगा।"

धार्मिक आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक समरसता को बल मिलता है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही भूमि है जहां प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का अधिकांश समय व्यतीत किया। माता शबरी के जूठे बेरों की महिमा आज भी जीवंत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक समरसता को बल मिलता है। वे रायगढ़ जिले के बरगढ़ खोला अंचल के ग्राम-खम्हार में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में को सम्बोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि इस कथा का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माताश्री हीराबेन मोदी की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से प्रदेश की जनता के लिए सुख, समृद्धि के लिए

कामना की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास श्री कृष्णा दुबे महाराज से भेंटकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से बना प्रसाद अर्पित किया गया, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक दो वर्षों में 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 19 चिन्हित तीर्थ स्थलों की यात्रा कराते हुए अब तक 5 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम को वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया। श्री शिव महापुराण कथा का वाचन अकोला (महाराष्ट्र) से पधारे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास श्री कृष्णा दुबे महाराज द्वारा संगीतमय शैली में किया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया और श्रीमती कमलेश जांगड़े राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा गबेल, रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष खरसिया कमल गर्ग सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

म.प्र. यूथ गेम्स 2025 में ट्रायथलॉन खेल को जोड़ने की मांग

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। म.प्र. यूथ गेम्स- 2025 में ट्रायथलॉन खेल जोड़ने की मांग कई बार की गई है परन्तु ट्रायथलॉन खेल को यूथ गेम्स की सूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2013 में आयोजित मुख्यमंत्री खेलों में ट्रायथलॉन खेल शामिल था जिसे बोट क्लब, बड़ा तालाब एवं वन विहार रोड में आयोजित किया गया था। ट्रायथलॉन खेल ओलम्पिक खेल है, जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत खेलों की सूची में शामिल है। ट्रायथलॉन खेल की एकेडमी म.प्र. शासन द्वारा संचालित है। म.प्र. के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न पदक अर्जित कर रहे हैं। यूथ गेम्स 2025 में कई खेल ऐसे है जो प्रदेश के एक दो जिलों में ही खेल जाते हैं तथा कई खेल अधिकृत खेल नहीं हैं, जिन्हें भी यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। म.प्र. ओलम्पिक संघ को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश ट्रायथलॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव जे.पी. सक्सेना ने मांग की है कि म.प्र. यूथ गेम्स 2025 में ट्रायथलॉन खेल को भी जोड़ा जाये। आपके ट्रायथलॉन खेल को यूथ गेम्स में जोड़ने से ट्रायथलीट खिलाड़ियों के उत्साह में बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश के खेल मंत्री और संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी मध्यप्रदेश ट्रायथलॉन एसोसिएशन ने कई बार पत्र लिखा है।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की शह पर बेलगाम इंटेलीजेंस आईजी अमित कुमार

(पेज 1 का शेष)

यह तो वह मामले है जो ज्यादा सुर्खियों में रहे। इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं जिससे सरकार की छबि खराब हुई है। अमित कुमार जैसे अधिकारी के कारण सरकार की छबि धूमिल हो रही है। बावजूद इसके सरकार का गृह विभाग अमित कुमार पर पर्दा डाले हुए है। अमित कुमार इंटलीजेंस के नाम पर सरकार के आंख में धूल झोंक रहे हैं। कारण भी स्पष्ट है कि प्रदेश के गृहमंत्री चाहते हैं कि सरकार किसी न किसी मामले में सरकार की किरकिरी हो और उन पर आंच भी न आये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी की पूरा दुरूपयोग गृहमंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। कई मामलों में आंख में धूल झोंककर मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है। साय को गृहमंत्री की करतूतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वह घटनाएं जिनसे सरकार छवि हुई धूमिल

बलौदा बाजार घटना: 10 जून 2024 को सतनामी समाज ने गिरौदपुरी से लगे महकोनी स्थित अमर गुफा में जोड़ा जैतखाम काटे जाने की घटना और उस पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था। विरोध-प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बेकाबू हो गए और देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आग लगा दी थी। इसके अलावा संयुक्त कार्यालय और तहसील कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई थी।

कांकेर में धर्मांतरण मामला: कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में हिंसा हुई थी। यहां एक धर्म परिवर्तित महिला के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया था। महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हिंसा हो गई थी। घटना में एडिशनल एसपी का सिर फूटा था।

रायगढ़ में कोल खदान के खिलाफ प्रदर्शन: रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के कोल खदान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लेडी कॉन्स्टेबल के साथ अभद्रता की थी। उसकी वर्दी फाड़कर खेतों में घसीटा था। दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। लेडी कॉन्स्टेबल आबरू बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। JPL कोयला खदान सेक्टर-1 कोल ब्लॉक के विरोध में 14 गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे थे।

होटलों में रेड डलवायी और फिर माफी मांगी: अमित कुमार ने रायपुर में होटल में छापा मारने के लिए रायपुर एसपी से बोला। फिर दबाव आया तो सभी से माफी मॉंगी। इससे पुलिस प्रशासन की काफी थू-थू हुई थी और अमित कुमार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको बता दें कि रायपुर में नेताओं के बड़े-बड़े होटल हैं।

मनमानी पोस्टिंग और तबादले में भ्रष्टाचार

छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में से 15 जिलों में पुलिस अधीक्षक राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा को दरकिनार करते हुए इन जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसपी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के इशारों पर नाचते हैं। अंबिकापुर, गरियाबंद, बिलासपुर कोंडगांव, कवर्धा, बेमतरा, पेंड्रा, रायपुर, दुर्ग, गौरेला, जांजगीर चापा, सक्ति, बैंकुण्ठपुर आदि जिलों में प्रमोटी एसपी हैं। जबकि नियम के अनुसार पुलिस अधीक्षक की पोस्ट आईपीएस सेवा से होना चाहिए लेकिन सूत्रों का कहना है कि अमित कुमार अयोग्य अफसरों की पोस्टिंग में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अमित कुमार 1-1 पोस्टिंग में 1-1.5 करोड़ कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सीधे आईपीएस पोस्टिंग के लिए पैसे नही देते। पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन अमित कुमार करते हैं।

डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन मामले में संदिग्ध है अमित कुमार की चुप्पी

डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन विवाद में हर दिन नये मोड़ सामने आ रहे हैं। वहीं इंटेलीजेंस के आईजी अमित कुमार की चुप्पी भी कई सवाल पैदा कर रही है। है। इस समय रायपुर का यह मामला काफी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि कारोबारी दीपक टंडन अपनी आय-व्यय का पूरा ब्यौरा पुलिस को सौंप चुके हैं। यह भी जानकारी सामने आई है, कि कल्पना वर्मा रकम के लेन-देन के अलावा "नक्सली उन्नमूलन गोपनीयता" भंग करने और दंतेवाड़ा में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप्प पैनल संचालित करने से जुड़ी क़वायतों को लेकर बार-बार अपना बयान बदल रही हैं। दरअसल कल्पना वर्मा ने कारोबारी टंडन पर पिता के साथ 75 लाख के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। इस रकम के लेन-देन संबंधी तथ्यों को लेकर संदेही डीएसपी नए-नए ऐसे बयान दे रही है, जो किसी के गले नहीं उतर पा रहे हैं। प्यार, तकरार, कारोबार और अब अपराध की ओर रुख कर रहे डीएसपी कल्पना वर्मा V/S दीपक टंडन मामले ने छत्तीसगढ़ पुलिस को सुर्खियों में ला दिया है। इस प्रकरण से पुलिस तंत्र में वर्दी के भीतर अपराधीकरण की "बू" आने लगी है। कल्पना वर्मा, दीपक टंडन को अपने पॉवर के बल पर कानूनी उलझनों में फंसाना चाहती है। दूसरी तरफ देखा जाये तो अमित कुमार की इस मामले में चुप्पी संदेह के घेरे में है।

सम्पादकीय

भोपाल का स्लॉटर हाउस कांड संवेदनहीन सत्ता और जवाबदेही का सवाल

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो हलचल मची हुई है, उसका केंद्र बना है भोपाल का बहुचर्चित स्लॉटर हाउस कांड। यह मामला केवल एक प्रशासनिक अनियमितता या स्थानीय भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। जिस प्रकार यह पूरा प्रकरण सामने आया और जिस तरह से इसमें राजनीतिक संरक्षण की परतें खुलती गईं, उसने आम जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है। भोपाल जैसे संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक शहर में स्लॉटर हाउस को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं, परंतु इस बार मामला कहीं अधिक गंभीर है। आरोप यह है कि नियमों की खुली अवहेलना करते हुए न केवल अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिला, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी आँखें मूँद ली गईं। सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब चलता रहा? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर मौन साधा गया? इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि जब मामला सार्वजनिक हुआ, तब भी सत्ता पक्ष की ओर से प्रारंभिक प्रतिक्रिया टालमटोल और बचाव की रही। यही रवैया राजनीतिक संकट को और गहरा करता है। लोकतंत्र में सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, न कि अपने पदों और सहयोगियों की ढाल बनने की। यदि कहीं भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई अनिवार्य है- चाहे वह कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। स्लॉटर हाउस केवल एक व्यावसायिक इकाई नहीं होता, उससे जुड़े होते हैं पर्यावरणीय मानक, स्वच्छता, पशु संरक्षण कानून और स्थानीय सामाजिक संवेदनाएँ। यदि इन सबकी अनदेखी कर किसी भी प्रकार की गतिविधि चल रही थी, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भोपाल की जनता लंबे समय से इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग करती रही है, परंतु उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस कांड ने सत्ता और स्थानीय निकायों के बीच की मिलीभगत को उजागर किया है। नगर निगम से लेकर विभागीय अधिकारियों तक की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं। यदि सरकारी मशीनरी ही नियमों को दरकिनार कर दे, तो फिर आम नागरिक से कानून पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राजनीति का उद्देश्य जनसेवा और सुशासन होना चाहिए, लेकिन जब वही राजनीति संरक्षण और दबाव का माध्यम बन जाए, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इस मामले में भी यही दिखाई दे रहा है- जहाँ जिम्मेदारी तय करने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि दोषियों पर कब तक और कितनी सख्ती होगी? जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। जाँच की प्रक्रिया पारदर्शी हो, दोषियों के नाम सार्वजनिक हों और यदि राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जाए। यह केवल एक शहर का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में शासन की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय बन चुका है। भोपाल का स्लॉटर हाउस कांड सत्ता को यह स्पष्ट संदेश देता है कि प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति अब अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। यदि सरकार सचमुच सुशासन और नैतिक राजनीति का दावा करती है, तो उसे इस मामले में उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यह कांड आने वाले समय में जनाक्रोश का बड़ा कारण बन सकता है।

सियासी गहमागहमी

कमलनाथ फिर मैदान में विकास की स्मृतियों का पुनर्पाठ

राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज है। जब सत्ता हाथ में हो तो विकास "प्रक्रिया" कहलाता है और जब सत्ता दूर हो जाए तो वही विकास "संकल्प" बन जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का छिंदवाड़ा के विकास में फिर से सक्रिय होना इसी शाश्वत राजनीतिक परंपरा का ताजा संस्करण है। छिंदवाड़ा से उनका रिश्ता किसी चुनावी परिचय भर का नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही राजनीतिक विरासत जैसा है। फर्क बस इतना है कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि "विकास के संरक्षक" की भूमिका में हैं। सड़कें पहले भी बनी थीं, अब फिर बनेंगी; योजनाएँ पहले भी आई थीं, अब फिर याद दिलाई जाएँगी। जनता भी समझदार है- वह जानती है कि चुनावी मौसम में विकास की फाइलों में अचानक ऑक्सीजन भर जाती है। दरअसल, राजनीति में सक्रियता का यह नया अध्याय बताता है कि सत्ता भले छिन जाए, पर क्षेत्र नहीं छूटता। कमलनाथ फिर से वही कर रहे हैं जो हर अनुभवी नेता करता है। जनता को याद दिलाना कि विकास की असली कॉपी अभी भी उनके पास सुरक्षित है।

भोपाल के मछली कांड में राजनीति की गंध

भोपाल में मछलियाँ कम थीं या विवाद ज्यादा यह तो जाँच का विषय है, पर इतना तय है कि "मछली कांड" ने राजनीति के तालाब में खूब छींटे उछाले। और जब छींटे ज्यादा उछलते हैं, तो किसी न किसी को फटकार का जाल जरूर घेर लेता है। इस बार यह जाल आकर अटका विश्वास सारंग के पाले में। मामला चाहे प्रशासनिक लापरवाही का हो या जिम्मेदारियों के फिसलन भरे घाट का, पर राजनीति ने इसे पूरी तरह "सार्वजनिक जलक्रीड़ा" बना दिया। विपक्ष ने इसे हाथोंहाथ लिया, मानो कोई बड़ी व्हेल पकड़ ली हो। सत्ता पक्ष सफाई देता रहा कि सब कुछ नियमों के जाल में ही तैरा था, लेकिन जनता को तो वही दिखा—जहाँ मछली कम, गंध ज्यादा थी। फटकार भी कम दिलचस्प नहीं रही। जैसे स्कूल में शिक्षक शरारती छात्र को डाँटता है- "आगे से ध्यान रखना!" राजनीति में यह वाक्य असल में होता है- "अब संभलकर तैरो।" मछलियों से ज्यादा तैराकी नेताओं को करनी पड़ रही है बयानबाजी की, बचाव की और जिम्मेदारी से बच निकलने की। अब देखना यह है कि यह मामला सचमुच साफ़ पानी तक पहुँचता है या फिर हमेशा की तरह फाइलों के गहरे तालाब में चुपचाप डुबकी लगा लेता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल
पानी मे जहर, हवा मे जहर, दवा मे जहर, जमीन मे जहर,
और, जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर!
कुछ इस तरह इस मॉडल मे गरीबो की मौतो के लिए कोई भी जिम्मेदार नही होता।
सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले - दोषियो को सजा और पीड़ितो को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कल 17 जनवरी को इंदौर पहुँच कर दूषित जल पीने से मारे गए लोगो के परिजनो से मुलाकात करेंगे। इंदौर मे दूषित पानी पीने से 20 से अधिक लोगो की मृत्यु सिर्फ़ एक दुर्घटना नही है बल्कि भाजपा सरकार के राज मे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण हुई राजनैतिक हत्या है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

मुरली मनोहर जोशी: वैचारिक दृढ़ता और संगठनात्मक समर्पण का जीवन

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका महत्व केवल पदों से नहीं, बल्कि उनके विचारों और दीर्घकालीन योगदान से आँका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ऐसा ही एक नाम हैं। वे उन नेताओं में हैं जिन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का दायित्व माना। डॉ. जोशी का जन्म 5 जनवरी 1934 को दिल्ली में एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में बीता। बचपन से ही वे मेधावी, जिज्ञासु और अनुशासित रहे। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में एम.एससी. और तत्पश्चात पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वे लंबे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक रहे। शिक्षा और अध्यापन ने उनके व्यक्तित्व में तार्किकता, स्पष्टता और वैचारिक अनुशासन का समावेश किया। छात्र जीवन के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और संघ के राष्ट्रवादी विचारों से गहरे प्रभावित हुए। संघ के माध्यम से उनमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना सशक्त हुई, जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित की। 1970 के दशक में वे सक्रिय रूप से भारतीय जनसंघ से जुड़े। आपातकाल के समय उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जेल भी गए। यह दौर उनके राजनीतिक जीवन की वैचारिक दृढ़ता का प्रमाण बना। जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी में विलय के बाद वे पार्टी के प्रमुख वैचारिक स्तंभों में शामिल हुए। 1991 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह वह समय था जब भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रही थी। उनके नेतृत्व में पार्टी ने वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक विस्तार दोनों में मजबूती प्राप्त की। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 'एकता यात्रा' का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देना था। इस यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना उनके साहस और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक माना गया।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में डॉ. जोशी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया (1998–2004)। इस कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दृष्टि को सशक्त करने का प्रयास किया। पाठ्यक्रमों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा के संतुलित समावेश पर उन्होंने विशेष बल दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। वे मानते थे कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का आधार होनी चाहिए। डॉ. जोशी विज्ञान और भारतीयता के समन्वय के समर्थक रहे। वे अक्सर कहते थे कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं को आधुनिक शोध से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने स्वदेशी चिंतन को भी प्रोत्साहित किया और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को प्रारंभिक दौर में ही मुखर रूप से सामने रखा।

संसदीय जीवन में वे कई बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वे एक प्रभावशाली वक्ता और गंभीर विचारक के रूप में जाने जाते हैं। संसद में उनके भाषण तथ्यों, इतिहास और वैचारिक गहराई से परिपूर्ण होते थे। डॉ. जोशी का व्यक्तित्व सादगी, विद्वत्ता और राष्ट्रनिष्ठा का संगम है। वे राजनीति में शुचिता और सिद्धांतों के पक्षधर रहे। भले ही समय के साथ वे सक्रिय राजनीति से कुछ दूर हुए हों, परंतु भाजपा की वैचारिक यात्रा में उनका योगदान स्थायी है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने शिक्षा, विचार और राष्ट्रवाद को एक सूत्र में पिरोते हुए सार्वजनिक जीवन जिया। उनका जीवन समर्पण, वैचारिक स्पष्टता और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का प्रेरक उदाहरण है।

19 जनवरी: 'ओशो दिवस' पर विशेष

"जियो, हंसो और प्रेम करो; यही सबसे बड़ा ध्यान है।"

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

36 वर्ष पहले, 19 जनवरी 1990 को पुणे में एक असाधारण चेतना ने अपनी देह का त्याग किया। आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया 'ओशो' के नाम से जानती है, वे केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, एक ऐसी विचार-क्रांति थे जिन्होंने मनुष्य को 'स्वयं होने' का साहस दिया। इस विशेष दिन को पूरा विश्व और ओशो के अनुयायी 'ओशो दिवस' के रूप में मनाते हैं। ओशो ने धर्म, ध्यान और जीवन के अर्थ को एक नई और जीवंत दृष्टि दी, एक ऐसी दृष्टि, जिसकी प्रासंगिकता आज की जटिल और बेचैन दुनिया में और भी गहरी हो गई है। उनके प्रवचनों के हजारों संकलन उपलब्ध हैं, पर उनका मूल सार यही है कि "जियो, हंसो और प्रेम करो; यही सबसे बड़ा ध्यान है।" ओशो के अनुसार धार्मिकता किसी संस्था से नहीं, बल्कि जागरूकता से जन्म लेती है। उन्होंने ध्यान को मंदिर-मस्जिद की सीमाओं से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुँचाया। उनके अनुसार ध्यान केवल आँख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर कार्य चलना, खाना, काम, प्रेम को होशपूर्वक करना है।

आज का युवा: शोर में शांति की तलाश

आज का युवा सूचना के विस्फोट, करियर की अनिश्चितता और मानसिक तनाव के नीचे दबा हुआ है। ऐसे समय में अतीशा के सूत्रों पर आधारित ओशो के प्रसिद्ध प्रवचन-संग्रह 'सहज जीवन' (The Book of Wisdom) का यह विचार किसी संजीवनी की तरह है: "ध्यान मन को शांत करने का प्रयास नहीं, बल्कि मन के पार जाने की कला है।" युवा जिस बेचैनी को समस्या मानते हैं, ओशो उसे ऊर्जा कहते थे एक अनगढ़ शक्ति जिसका रूपांतरण केवल जागरूकता से संभव है। भय और साहस पर दिए गए उनके विचारों के संकलन में उल्लेख है कि "भय वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर कैद किए रहती है।" आज जब तुलना, असफलता और अनिश्चितता का दबाव हर युवा को घेरे हुए है, ओशो सिखाते हैं कि भय का समाधान किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि स्वयं की स्वीकारोक्ति और भीतर की शांति में है।

'जोर्बा द बुद्ध': भौतिकता और अध्यात्म का अनूठा मिलन

ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार था- 'जोर्बा द बुद्ध'। 'जोर्बा' यूनानी साहित्य का वह पात्र है जो सांसारिक आनंद और उत्सव का प्रतीक है, जबकि 'बुद्ध' परम मौन और ध्यान के प्रतीक हैं। ओशो ने इस पर इसलिए जोर दिया क्योंकि वे एक ऐसे 'नये मनुष्य' का निर्माण करना चाहते थे जो बाहर से समृद्ध (जोर्बा) और भीतर से शांत (बुद्ध) हो। उनके अनुसार, शरीर और आत्मा का यह संतुलन ही मनुष्य की पूर्णता है। उनकी पुस्तक 'जीवन के रहस्य' में वे स्पष्ट करते हैं कि आनंद कोई विलासिता नहीं, बल्कि मनुष्य की मौलिक प्रकृति है। आज के समाज के लिए यह विचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं- जीवन के भीतर उतरकर ही उसे जीता जाता है।

रिश्तों में स्वतंत्रता का उत्सव

रिश्तों पर ओशो की दृष्टि अत्यंत आधुनिक थी। उन्होंने प्रेम को 'स्वामित्व' नहीं, बल्कि 'स्वतंत्रता' का नाम दिया। तंत्र सूत्रों पर आधारित उनके प्रसिद्ध प्रवचन संग्रह 'The Book of Secrets' में वे रेखांकित करते हैं कि रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब वे दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन हों। आज जब अपेक्षाएँ, नियंत्रण और गलतफहमियाँ रिश्तों को जकड़ रही हैं, ओशो का यह विचार एक स्वस्थ, परिपक्व और सम्मानपूर्ण संबंध की राह दिखाता है। उनकी पुस्तक 'From Bondage to Freedom' इस बात पर बल देती है कि समाज बदलने का मार्ग व्यक्ति की अपनी चेतना के रूपांतरण से होकर गुजरता है। उनकी प्रसिद्ध 'डायनेमिक मेडिटेशन' ने आधुनिक मनुष्य के तनाव, दबी भावनाओं और मानसिक बोझ को मुक्त करने का एक वैज्ञानिक और प्रभावी मार्ग दिया।

'ओशो' नाम का दर्शन और अनुभूति

अक्सर पाठकों के मन में जिज्ञासा होती है कि रजनीश 'ओशो' कैसे बने? दरअसल, वर्ष 1989 में उन्होंने स्वयं के लिए 'ओशो' शब्द चुना, जो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स की 'ओशनिक फीलिंग' (Oceanic Feeling) की अवधारणा पर आधारित है। ओशो ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट किया था कि यह नाम किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक 'अनुभव' का संबोधन है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर स्वयं सागर हो जाती है, वैसे ही 'ओशो' उस अवस्था का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है और वह संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाता है।

क्यों जरूरी हैं ओशो?

आज की पीढ़ी के पास असीम ऊर्जा है, पर वह ऊर्जा भीतर के शांत केंद्र तक कैसे पहुँचे इसका मार्ग ओशो के दर्शन में मिलता है। ओशो को पढ़ना किसी पंथ को मानना नहीं; बल्कि स्वयं को जानने और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाने की एक साहसी शुरुआत है। वे मौन में खिलती वह क्रांति हैं, जो मनुष्य को बाहरी बंधनों से नहीं उसकी अपनी भीतरी दीवारों से मुक्त करती है।

उच्च शिक्षा संस्थान में संभावना की मौत

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सरकारी महाविद्यालय में तीन छात्राओं द्वारा एक छात्रा की रैगिंग और प्राध्यापक द्वारा यौन उत्पीड़न का शर्मनाक मामला सामने आया है। छात्रा की 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित मृतिका के पिता ने पुलिस को की शिकायत में कहा है कि कॉलेज की तीन वरिष्ठ छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग करते हुए मारपीट की। इसी समय प्राध्यापक अशोक कुमार ने बेटी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए यौन उत्पीड़न किया। इस दोहरी प्रताड़ना से बेटी की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उपचार का चलते मौत हो गई। देश के शिक्षा संस्थानों में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कोई छात्रा अपना भविष्य उज्वल बनाने के लिए कॉलेज जाए और वहां उसे निर्ल्लज बेहूदी हरकतों का सामना करना पड़े। जबकि सभी शिक्षा संस्थानों में रैगिंग पर क़ानूनी रोक है। बावजूद प्रताड़ना की घटिया घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। इससे भी जयदा हैरानी में डालने वाली बात यह है कि जिस शिक्षक को रैगिंग रोकने की नैतिक जुम्मेबारी थी,वह खुद यौन उत्पीड़न करने लग गया।

इसे उच्च शिक्षा संस्थानों की विडंबना ही कहा जाएगा कि अब तक गुरुओं की प्रताड़ना के चलते शिष्यों की आत्महत्याओं के मामले सामने आते रहे हैं, किंतु अब अपनी पुत्री समान छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले भी सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं। ओड़ीसा के बालासोर में यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्यवाही न होने से परेशान छात्रा ने आत्मदाह कर ली थी। इसी तरह बैंग्लुरु में दो शिक्षक हवस पूर्ति के लिए हैवान बन गए। इन शिक्षकों ने छात्रा को नोट्स देने के लिए बुलाया और दुष्कर्म किया। कोलकाता के आईआईएम की एक मनोवैज्ञानिक महिला परामर्शदाता के साथ छात्रावास में कथित दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था। उच्च शिक्षा परिसरों के ये मामले चिंता के साथ शर्मसार करने वाले हैं। इन संस्थानों में प्रताड़ना के चलते आत्महत्या के मामले भी नहीं थम रहे है। नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में दंत चिकित्सा की छात्रा ने छात्रावास के अपने कक्ष में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। यह अत्यंत बैचेन करने वाला विषय है कि उच्च शिक्षा के लिए हम विदेशी विवि भारत में खोलने के फैसले ले रहे हैं, दूसरी ओर हम अपनी शिक्षा संबंधी नीतियों में पश्चिम का जरूरत से ज्यादा अनुकरण कर रहे हैं। जबकि हमें अपने ही संस्थानों में बुनियादी सुधार की जरूरत है। यदि हम विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे तो छात्र एवं अभिभावक देशी संस्थानों को दोयम दर्जे का मानने लग जाएंगे। वैसे भी विदेशों में पढ़ाई के चलते प्रतिभाओं के पलायन का संकट खड़ा हो रहा है। शिक्षकों द्वारा दुष्कर्म और प्रताड़ना के बढ़ते मामलों से तय होता है कि एक तो हमारे शिक्षक वैभव और भोग की हसरतें पालने लगे हैं, दूसरे वे छात्रों में उम्मीदों की उड़ान पैदा करने की बजाय निराशा, कुंठा और अवसाद पैदा कर रहे हैं। लगता है शिक्षकों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी कोई उत्साहजनक असर नहीं पड़ा है। अन्यथा इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटनाएं घटती ही नहीं।

21वीं सदी को ज्ञान की सदी की संज्ञा दी गई है। ज्ञान परंपरा और मातृभाषाओं में शिक्षा दिए जाने की बात भी खूब जोर-शोर से उठी है। शिक्षा की पूंजी से गरीब और वंचित के लिए उच्च पद, बड़ा उद्योगपति और विश्वस्तरीय तकनीकिशियन (टेक्नोक्रेट) बनने के रास्ते भी खुले हैं। बावजूद शिक्षा संस्थाओं से दुश्कर्म, पलायन और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं तो यह चिंतनीय पहलू है। क्योंकि शिक्षा के जरिए विद्यार्थी और उसके अभिभावक जिस उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने की परिकल्पना कर रहे होते हैं, यदि इसी बीच संभावना की मौत हो जाए, तो यह शिक्षा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। ज्ञान की महिमा ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है कि शिक्षा पर जाति, नस्ल या रक्त विशेष समुदायों का ही अधिकार है। राजतंत्र में यह धारणा सदियों तक फलीभूत होती रही है कि भारत समेत दुनिया का कुलीन वर्ग नियति की देन है। जबकि वाकई यह पक्षपाती व्यवस्था की उपज रही है। ज्ञान के तंत्र ने इस भ्रामक स्थिति को तोड़ने का काम किया है। हालांकि भारतीय मनीषियों ने ज्ञान की इस शक्ति को हजारों साल पहले जान लिया था, इसीलिए कहा भी गया कि राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, जबकि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ज्ञानार्जित विद्वता की ही देन है कि आज दुनिया शिक्षा और अनुसंधान से आविष्कृत ऐसा तकनीकि संसार रच रही है, जिसमें सुविधाएं मुट्ठी में हैं और लक्ष्य अंतरिक्ष में मनुष्य को बसाने की संभावनाएं तलाश रहा है। संभावनाओं के इस द्वार पर शिक्षा परिसरों में छात्र निराशा के भंवर में मौत का लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो यह समूची शिक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है?

देश के युवाओं की ये मौतें, संभावनाओं की मौतें हैं। ऐसे में यदि छात्र एवं छात्राओं की मौतों का यही सिलसिला बना रहता है तो देश के बेहतर भविष्य की संभावना क्षीण हो जाएगी? ये मौतें अध्ययन-अध्यापन से उपजी परेशानियों के चलते सामने आ रही हैं। बावजूद देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दलों के रहनुमा मौतों को केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लिहाजा समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल होती नहीं दिख रही है। यदि आने वाले समय में छात्र आत्महत्याओं को शिक्षा की व्यापक समझ के परिदृश्य में नहीं देखा गया तो इन मौतों पर विराम लग जाएगा यह कहना मुश्किल है?

देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा तक शिक्षण पद्धति को लेकर अजीब भ्रम, विरोधाभास व दुविधा की स्थिति बनी हुई है। नतीजतन इससे उबरने के अब तक जितने भी उपाय सोचे गए, वे शिक्षा के निजीकरण, अंग्रेजीकरण और विदेशीकरण पर जाकर सिमटते रहे हैं।यही वजह रही कि देश में शिक्षा में आवश्यक बदलाव लाने की दृष्टि से आयोग तो बिठाए गए,उनकी रपटें भी आईं,लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। लिहाजा शिक्षा प्रणाली में आदर्श व समावेशी शिक्षा के बुनियादी तत्व में शामिल करने की बजाय, शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो केवल और केवल अंग्रेजीकरण की पर्याय बनती जा रही है। नतीजतन शिक्षा सफलता के ऐसे मंत्र में बदल गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना रह गया है। दुष्चक्र में फंसी इस शिक्षा की यही बानगियां इन घटनाओं में देखने में आ रही हैं।

कोटा के कोचिंग संस्थानों में निरतंत छात्रों द्वारा की जा रही खुदकुशियों की पड़ताल करने से पता चलता है कि छात्रों को अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार महान बनाने की होड़ में लगे हैं। केरल के रहने वाले छात्र अनिल कुमार ने आत्महत्या पूर्व लिखे पत्र में लिखा था, 'सॉरी मम्मी-पापा, आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन मैनें इसकी कद्र नहीं की।' यह पीड़ादायी कथन उस किशोर का था, जो आईआईटी की तैयारी में जुटा था। ये संस्थान प्रतिभाओं को निखारने का दावा अपने विज्ञापनों में खूब करते हैं। लेकिन युवाओं को महान और बड़ा बनाने का सपना दिखाने का इस उद्योग का दावा कितना खोखला है, यह पता यहां बढ़ती जा रही आत्महत्याओं से चलता है। शिक्षा के इस कोचिंग उद्योग का गोरखधंधा देशव्यापी है। इसकी जकड़न में अब अन्य प्रदेशों के बड़े नगर भी आते जा रहे हैं।

उत्तराखंड जन–जन तक सरकार, हर समस्या का समाधान....

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक 20,814 शिकायतों का निराकरण

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और जनोन्मुखी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसमस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। सरकार सीधे जनता तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। प्रदेश के सभी जनपदों में अब तक पिछले दिवस तक 328 शिविरों का आयोजन किया जा चुका था, इस प्रकार कुल मिलाकर 347 शिविरों के माध्यम से जनता को सीधे प्रशासनिक सेवाओं से जोड़ा गया है। इन शिविरों में पिछले दिवस तक 2,54,137 नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

कुल प्रतिभागियों की संख्या 2,77,654 तक पहुँच गई है। यह आँकड़ा जनविश्वास और सरकार की पहुँच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जनसमस्याओं के समाधान की दृष्टि से भी यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। अब तक 20,814 शिकायतें प्राप्त हो चुकी थीं, जिनमें आज 1,479 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 22,293 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 18,168 शिकायतों का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका था तथा आज 807 शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे कुल 18,973 शिकायतों का सफल निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। यह उपलब्धि सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली और जवाबदेही को रेखांकित करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को प्रमाण पत्र एवं लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी निरंतर गति से आगे बढ़ी है।

36,753 प्रकरणों में पूर्व में लाभ प्रदान किए गए थे, जबकि आज 1,502 नए मामलों में प्रमाण पत्र अथवा लाभ वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 38,255 नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जो सेवा वितरण की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

1,38,011 नागरिक पूर्व में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो चुके थे। इस प्रकार कुल 1,51,565 नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह अभियान उसी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है।

कटते वन, मिटती धरती

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में आदिवासी जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विनाश तेज है। सारंडा जंगलों में नक्सली गतिविधियाँ और अरावली पहाड़ियों में खनन जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। इससे बाढ़, सूखा और प्रदूषण बढ़ रहा है, जो पर्यावरणीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। वनों की कटाई और विनाश आज न केवल हमारे पर्यावरण के लिए खतरा हैं, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी एक घातक चेतावनी बन चुके हैं। जब हम कहते हैं "जंगल का विनाश मतलब संपूर्ण विनाश," तो यह महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक दहकती हुई आग पर चेतावनी की तरह है। इस विनाश के नाटकीय परिणाम धीरे-धीरे प्रवाहमान जीवन को थाम रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में ह्रास, मिट्टी का कटाव, जलवायु असंतुलन, और अंततः मानव स्वास्थ्य एवं आजीविका पर अकल्पनीय असर। आज का यह लेख उसी गंभीर अलार्म की प्रतिध्वनि है और हमारे जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए एक व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत करता है।

जंगल सिर्फ पेड़-पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जटिल जीवन-समूह है जो अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को संजोए हुए है। हर पौधा, कीट, पक्षी, स्तनपायी, और सूक्ष्म जीव मिलकर एक संतुलित व्यवस्था बनाते हैं। ये जीव-जंतु न केवल ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन अवशोषण का काम करते हैं, बल्कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने, जल चक्र को नियमित करने, और तटीय एवं पहाड़ी भूस्खलनों को रोकने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, औषधीय जड़ी-बूटियों, खाद्य एवं वृक्षारोपण उत्पादों के रूप में वनों ने मानव सभ्यता को सदियों से पोषण दिया है। वर्तमान समय में वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है। हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक वनों का सफाया किया जाता है। कृषि के विस्तार, आवासीय और औद्योगिक विकास, अवैध वृक्षतोड़, कोयला एवं खनिज उत्खनन, और मनोवैज्ञानिक लाभार्थी (जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन) की मांग, इन सभी ने मिलकर जंगलों की कमर तोड़ दी है। पेड़ों के कटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जो ग्रीनहाउस प्रभाव को तीव्र करता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण बाढ़, सूखा, हीटवेव और चक्रवात जैसी आपदाएँ बढ़ रही हैं। विश्व के जैव विविधतम क्षेत्रों में से एक अमेजन और कांगो बेसिन जैसे जंगलों में अब हजारों प्रजातियाँ लुप्ति की कगार पर हैं। इसका मतलब न केवल आनुवांशिक विविधता का ह्रास, बल्कि खाद्य सुरक्षा और औषधीय खोजों में भी कटौती। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। वनों के विनाश से उनका जीविकोपार्जन ध्वस्त हो रहा है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विस्थापन, गरीबी और संघर्ष को जन्म मिलता है। वनों का नुकसान सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी हानिकारक है। 'इको-एंजाइटी' नामक एक शोध ने साबित किया है कि हरा-भरा परिवेश इंसानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जब जंगल कटते हैं, तो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का नैतिक व मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। शहरीकरण और जंगलों की दूरी ने आधुनिक जीवनशैली को एकाकीपन, तनाव और अवसाद की ओर धकेल दिया है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठन वनीकरण (afforestation), पुनर्वनीकरण (reforestation), और निर्यात पर प्रतिबंध जैसे प्रयासों में जुटे हैं। भारत में हरित क्रांति के बाद से 'ग्रीन इंडिया मिशन', 'नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों ने वनों के क्षेत्र में कुछ इज़ाफ़ा किया है। परन्तु, ये प्रयास अक्सर असंयमित विकास की मांग और स्थानीय प्रवृत्तियों के दबाव में अधूरे रह जाते हैं। वृक्ष लगाने से समस्या हल नहीं होती; हमें उन्हें बचाए रखना भी है।

वन विनाश को रोकने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण और समग्र नीति-निर्माण की आवश्यकता है। हमें कुछ व्यवहार्य कदम उठाने चाहिए। जैसे पाठ्यक्रमों में पारिस्थितिकी और सतत विकास को अनिवार्य करना, ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय कार्यशालाएँ एवं अभियानों का आयोजन करना, वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी एवं वन-आश्रित समुदायों को संवैधानिक अधिकार और लाभ सुनिश्चित करना, 'जंगल दोस्तों' (Forest Guardian) कार्यक्रम लागू करना, जिससे स्थानीय लोग जंगल की सुरक्षा और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभा सकें, स्थानीय और मूल जाति (native species) के पौधे ही लगाना चाहिए जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, पारिस्थितिक गलियारा' (ecological corridors) बनाकर वन क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए जिससे जीव-जंतु अपनी पारगमन-मार्ग सुरक्षित रख सकें, शहरों के चारों ओर 'हरित प्रति' (greenbelt) बनाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण घटे और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे एवं शहरी बागवानी, छतों और दीवारों पर हरा-भरा पौधारोपण बढ़ावा देना चाहिए। "जंगल का विनाश मतलब संपूर्ण विनाश" में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह सत्य है कि जब वन समाप्त होंगे, तब न सिर्फ हमारी जैव विविधता, बल्कि हमारा पोषण, हमारा जलवायु, हमारा समाज और अंततः मानव सभ्यता स्वयं संकट में आ जाएगी। हमें आज ही, तत्काल, निर्णायक कदम उठाने होंगे। जागरूकता बढ़ाएँ, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएं, तकनीक और नवाचार को अपनाएँ, आणि शासन-व्यवस्था में दृढ़ परिवर्तन लाएँ। यदि हमने यह भूल किया कि हम और हमारे जंगल एक-दूसरे के पूरक हैं, तो हमें अपने अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाना होगा।

खेल विभाग की बड़ी पहलः खेलो एमपी चयन ट्रायल में उभरी ग्रामीण खेल प्रतिभाएँ

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। खेल विभाग द्वारा खेलो एमपी योजना के अंतर्गत चयन ट्रायल का सफल आयोजन टिमरनी स्थित एकेडमी हाइट्स पब्लिक स्कूल परिसर में किया गया। इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना रहा। खेल समन्वयक हिना अली ने बताया कि ट्रायल में कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, रस्सा कशी, पिट्ठू, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। एथलेटिक्स में 100, 200, 400 व 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, शॉटपुट, डिस्कस तथा भाला फेंक स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया। खो-खो, वॉलीबॉल एवं रस्साकशी में बिछापुर, टेमागांव एवं सेंट मैरी स्कूल की टीमों ने भाग लिया। खेल विभाग द्वारा चयनित खिलाड़ियों से ब्लॉक स्तरीय टीम का गठन किया गया। आयोजन में वॉलीबॉल संघ अध्यक्ष राजकुमार चंदेल, एकेडमी हाइट्स पब्लिक स्कूल के संचालक सचिन बलवाते प्राचार्य, खेल प्रशिक्षक दिलीप चौहान, आरती भिलाला, प्रियंका चंदेल, कुंदन कैथवास, अख्तर अहमद, राजनंदिनी धनोरे, कल्पना कौशल, निखत शाह, करण सोनी, विजेता ओसवाल एवं मोनिका चंदेल सहित अनेक लोगों का विशेष सहयोग रहा। खेल विभाग द्वारा चयनित खिलाड़ी अब 17 से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाली जिला स्तरीय खेलो एमपी प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। खेल विभाग की इस पहल से क्षेत्र में खेलों के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ी है।

राज्य स्तरीय जनजातीय जीवनशैली चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 21 फरवरी तक

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में 20 से 21 फरवरी तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन आदिम जाति विकास विभाग एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का विषय जनजातीय जीवनशैली है, प्रतियोगिता का आयोजन सबेरे 10 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से अनुसूचित जनजाति संवर्ग के प्रथम 150 पंजीकृत प्रतिभागियों को शामिल किया जायेगा। प्रस्तावित यह चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन के कैनवास के माध्यम से किया जायेगा। कैनवास चित्रकारी में 18 से 30 वर्ष एवं 30 वर्ष से अधिक दो अलग-अलग आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। केनवास में चित्रकारी करने के लिए प्रतिभागी को 20 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से 21 फरवरी शाम 4:00 बजे तक का समय उपलब्ध रहेगा। निर्णायक मण्डल द्वारा अंक पद्धति से प्रतिभागियों द्वारा बनायी गई पेंटिंग्स का मूल्यांकन किया जावेगा। प्रतियोगिता का परिणाम 21 फरवरी 2026 को घोषित किया जाएगा।

निजी स्कूल में नाबालिग के साथ हुआ गंदा काम

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। कोतवाली थाना नरसिंहपुर में दर्ज मामले में निजी स्कूल में नाबालिक से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिसने एक बार फिर शिक्षा के मंदिर के नाम पर दाग लगा दिया है। बताया जाता है कि नरसिंहपुर स्थित जय नरसिंह स्कूल में घटी घटना से एक बार फिर नरसिंहपुर के बेलगाम शिक्षा विभाग की काली करतूत लोगों के सामने उजागर आ गई है। कुछ सूत्रों ने बताया है कि इससे पूर्व में भी अभिभावक ने स्कूल में की थी शिकायत और यदि स्कूल प्रबंधन और स्कूल का संचालन करने वाली समिति तत्समय ही उचित कदम उठाए हो तो नाबालिक को इस तरह है और पीड़ा और दर्द नहीं झेलना पड़ता। जिससे स्पष्ट रूप से सही तरीके से सामने आ गया है स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की लापरवाही से घटी घटना में पहली नजर में भले ही स्कूल और समिति दोषी नजर आ रहे हैं परंतु गहनता से देखने पर नरसिंहपुर के शिक्षा विभाग के मुखिया जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक के साथ निजी स्कूलों को मान्यता देने वाली शाखा ही सबसे बड़ी दोषी है। क्योंकि जब जिले में पूर्व में भी नरसिंहपुर जिला मुख्यालय करेली और गाडरवारा जैसे नगरों में बच्चों के साथ छेड़छाड़ अश्लीलता और दुष्कर्म जैसे मामलों के साथ उनकी जान तक चली जाने की लापरवाही के केस दर्ज हो चुके हैं परंतु किसी भी निजी स्कूल पर आज तक थोड़ी सी भी कार्यवाही नहीं हुई है। क्या यह सब बिना किसी मोटी रकम या बंद लिफाफे के संभव है और यदि ऐसा है तो यह तो सरासर खुलेआम भ्रष्टाचार है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)